Azadi Ka Amrit Mahotsav

GURU DEEKSHAA IAS

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रो के लिए

1st September 2022

FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

Guru Deekshaa Hindi

INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

1st September 2022

1. - दलबदल विरोधी कानून के बारे में: 3

(i) दलबदल विरोधी कानून क्या है? 3

(ii) अयोग्यता के आधार निम्नलिखित हैं: 3

(iii) दलबदल के खिलाफ कानून किन मुद्दों का कारण बनता है? 4

(iv) विवाद में अध्यक्ष की भूमिका: 4

(v) विभाजन का कोई उल्लेख नहीं है: 4

(vi) मतदान के जनादेश को तोड़ा जा रहा है: 4

(vii) नियमित सरकारी कार्यों पर प्रभाव: 4

(viii) दल-बदल विरोधी कानून के संबंध में कौन-सी विभिन्न सिफारिशें मौजूद हैं? 4

(ix) आगे बढ़ने का रास्ता: 5

2. - मनरेगा का विवरण: 6

(i) के बारे में: 6

(ii) महत्वपूर्ण लक्ष्य: 6

(iii) मनरेगा कार्यक्रम के तहत लाभ के पात्र होने के लिए आवेदकों को नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करना होगा: 6

(iv) योजना के महत्वपूर्ण विवरण: 6

(v) ग्राम सभा क्या करती है? 7

(vi) मनरेगा के तहत राज्य सरकार के दायित्व: 7

3. - धन शोधन निवारण अधिनियम के बारे में: 8

(i) मनी लॉन्ड्रिंग: यह क्या है? 8

(ii) धन शोधन निवारण अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य हैं: 8

(iii) PMLA के तीन प्राथमिक लक्ष्य हैं: 8
(iv) विवाद समाधान: 8
(v) पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम 2012: 8

4. - प्रवर्तन निदेशालय का विवरण: 9
(i) प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जानकारी: 9
(ii) ऐतिहासिक संदर्भ: 9
(iii) दो क़ानूनों को लागू करना प्रवर्तन निदेशालय की ज़िम्मेदारी है: 9
(iv) संयोजन: 9
(v) अन्य सूचना: 9
(vi) विशेष अदालतें: 9

संपादकीय विश्लेषण 10

1. बैंकों का निजीकरण क्यों किया जाना चाहिए: 10
(i) निजीकरण के बारे में: 10
(ii) निजीकरण के लिए ये मकसद क्यों मौजूद हैं? 10
(iii) दीर्घकालिक परियोजना घटक: 10
(iv) क्या चिंताएँ संबंधित हैं? 11
(v) लेने के लिए कदम: 11

2. भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में: 12
(i) जनसांख्यिकीय लाभांश की परिभाषा: 12
(ii) भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश: 12
(iii) जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ: 12
(iv) जनसांख्यिकीय लाभांश में बाधाएं: 13
(v) क्या किया जाए? 13
(vi) लेने के लिए कदम: 14

1. - दलबदल विरोधी कानून के बारे में:

जीएस II

विषय→संसद से जुड़े मुद्दे

दलबदल विरोधी कानून क्या है?

- दल बदलने वाले विशिष्ट सांसद और विधायक दलबदल विरोधी अधिनियम के तहत दंड के अधीन हैं।
- इसे 1985 में संसद द्वारा संविधान की दसवीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य सांसदों को दल बदलने से हतोत्साहित करके राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना था।
- दसवीं अनुसूची, जिसे दलबदल विरोधी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, को 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।
- यह उन शर्तों को बताता है जिनके तहत निर्वाचित अधिकारी राजनीतिक दलों को बदलने पर सेवा करने के लिए अपात्र होते हैं।
- यह प्रतिक्रिया राज्य प्रशासन द्वारा 1967 के आम चुनावों के बाद पार्टी-होपिंग विधायकों द्वारा उखाड़ फेंके जाने पर की गई थी।
- हालांकि, यह सांसदों या विधायकों के एक समूह को दलबदल दंड का भुगतान किए बिना एक अलग राजनीतिक दल में शामिल होने (या साथ में शामिल होने) की अनुमति देता है। राजनीतिक दलों को भी दंडित नहीं किया जाता है यदि वे विद्रोही सांसदों का समर्थन या विरोध करते हैं।
- 1985 के अधिनियम ने एक "विलय" को एक निर्वाचित राजनीतिक दल के एक तिहाई सदस्यों के "दलबदल" के रूप में परिभाषित किया:
- 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इसे बदल दिया, और आज, पार्टी के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों को "विलय" का समर्थन करना चाहिए ताकि इसे वैध माना जा सके।
- कांग्रेस के सदस्य जो सदन में सेवा करने के लिए अपात्र हैं वे किसी भी राजनीतिक बैनर के तहत चुनाव में कार्यालय के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- उस सदन के सभापति या अध्यक्ष से दलबदल संबंधी निरर्हता के बारे में निर्णय लेने का अनुरोध किया जाता है, और फिर उन अनुरोधों की "न्यायिक समीक्षा" की जाती है।
- हालांकि, कानून एक समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है जिसके द्वारा पीठासीन अधिकारी को यह तय करना होगा कि एक दलबदल मामले में कार्रवाई की जाए या नहीं।

अयोग्यता के आधार निम्नलिखित हैं:

- यदि कोई निर्वाचित सांसद या विधायक स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग करता है।
- यदि वह पहले अनुमति प्राप्त किए बिना अपने राजनीतिक दल या अधिकार की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस सदन में मतदान से परहेज करता है या मतदान से दूर रहता है,
- उसे अयोग्य ठहराए जाने के लिए, घटना के 15 दिनों के भीतर उसकी पार्टी या नामित व्यक्ति द्वारा मतदान करने में उसकी विफलता की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति जो किसी दल की सहायता के बिना निर्वाचित हुआ है, ऐसा करने का चुनाव करता है।
- यदि कोई नामांकित व्यक्ति पहले छह महीने समाप्त होने के बाद अपनी पार्टी की संबद्धता बदलता है।

दलबदल के खिलाफ कानून किन मुद्दों का कारण बनता है?

प्रतिनिधि और संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करना:

- सांसद या विधायक पार्टी के मंच के अनुसार मतदान करने के लिए बाध्य हैं और दलबदल विरोधी क़ानून के पारित होने के बाद उन्हें अन्यथा करने की अनुमति नहीं है।
- दल-बदल विरोधी क़ानून के कारण, जो केवल सांसदों को अपने राजनीतिक दल के प्रति जवाबदेह ठहराता है, जवाबदेही की श्रृंखला टूट गई है।

विवाद में अध्यक्ष की भूमिका:

- जब सदन के अध्यक्ष या अध्यक्ष को दलबदल विरोधी मामलों में निर्णय लेना चाहिए तो क़ानून विशेष रूप से यह निर्धारित नहीं करता है।
- कानूनी मामले तीन से छह महीने तक कहीं भी चल सकते हैं। कुछ मामलों को समय बीतने के बाद सुलझा लिया जाता है।

विभाजन का कोई उल्लेख नहीं है:

- दल-बदल विरोधी क़ानून में अब 91वें संशोधन के कारण दल-बदल विरोधी निर्णयों के लिए एक अपवाद है।
- हालाँकि, संशोधन एक "विभाजन" के विपरीत एक विधायक दल के अंदर "विलय" को मान्यता देता है।

मतदान के जनादेश को तोड़ा जा रहा है:

- कहा जाता है कि विधायक दलबदल कर अपनी जनता की इच्छाओं की अवहेलना करते हैं, जब वे एक पार्टी के मंच पर चुने जाते हैं, लेकिन फिर निर्णय लेते हैं कि कैबिनेट पदों या वित्तीय लाभों के प्रलोभन के कारण किसी अन्य पार्टी में स्थानांतरित करना अधिक सुविधाजनक होगा।

नियमित सरकारी कार्यों पर प्रभाव:

- 1960 के दशक में, कुख्यात "आया राम, गया राम" नारा सांसदों के चल रहे दलबदल की प्रतिक्रिया में विकसित किया गया था।
- दलबदल राजनीतिक व्यवस्था को बाधित करता है और कार्यकारी शाखा पर प्रभाव डालता है।
- दलबदल से विधायकों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा मिलता है, जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के आदर्शों के विपरीत है।
- जबकि थोक परित्याग की अनुमति है, खुदरा दलबदल नहीं है। अंतराल को भरना होगा, इस प्रकार संशोधनों की आवश्यकता है।
- उन्होंने चिंता व्यक्त की कि भले ही एक राजनेता दल बदल सकता है, उन्हें नए में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए।

दल-बदल विरोधी कानून के संबंध में कौन-सी विभिन्न सिफारिशें मौजूद हैं?

- चुनाव आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि यह निकाय है जो यह तय करता है कि दलबदल की अनुमति दी जाए या नहीं।
- कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को दलबदल के आवेदनों पर सुनवाई करनी चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने दलबदल के मामलों में तेजी से और निष्पक्ष रूप से फैसला करने के लिए संसद को उच्च न्यायपालिका के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष पैनल बनाने की सलाह दी है।

- कुछ टिप्पणीकारों द्वारा कानून को असफल माना गया है, जिन्होंने इसे निरस्त करने का आह्वान किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का दावा है कि यह केवल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकारों के संरक्षण से संबंधित है।

आगे बढ़ने का रास्ता:

- वास्तव में एक राजनीतिक मामले को संभालने के लिए कानूनी प्रणाली का उपयोग करने के प्रयास से यह मुद्दा लाया गया है।
- यदि दल-बदल से प्रशासन की स्थिरता को खतरा है, तो पार्टियों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए।
- भारत में, राजनीतिक दल नियामक कानून की सख्त जरूरत है। इस तरह के उपाय से पार्टियों के भीतर पार्टी लोकतंत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए, राजनीतिक दलों को आरटीआई के तहत लाना चाहिए, आदि।

- प्रतिनिधि लोकतंत्र को कानून के नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए, दल-बदल विरोधी कानून को केवल उन कानूनों तक ही सीमित रखा जा सकता है जहां सरकार में विश्वास की हानि हो सकती है।

- ***स्रोत→ इंडियन एक्सप्रेस***

2. - मनरेगा का विवरण:

जीएस II

विषय→सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

के बारे में:

- कार्यक्रम "काम करने के अधिकार" की रक्षा के लिए एक प्रकार के सामाजिक हस्तक्षेप के रूप में बनाया गया था। ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, स्थानीय सरकार को अनुबंधित रूप से कम से कम 100 दिनों का वेतनभोगी रोजगार देना होगा।

महत्वपूर्ण लक्ष्य:

- अकुशल श्रम के लिए प्रत्येक स्वयंसेवक के लिए, कम से कम 100 दिनों के भुगतान वाले ग्रामीण रोजगार का उत्पादन किया जाना चाहिए।
- गरीब ग्रामीण समुदायों की आय धाराओं को बढ़ाकर सामाजिक समावेश को आक्रामक रूप से बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसे लंबे समय तक चलने वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- ग्रामीण-से-शहरी प्रवास की मात्रा को कम करना।
- ग्रामीण श्रम का उपयोग करें जिसका उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नहीं किया गया है।

मनरेगा कार्यक्रम के तहत लाभ के पात्र होने के लिए आवेदकों को नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करना होगा:

- एक भारतीय नागरिक जो नरेगा लाभ के लिए आवेदन करना चाहता है उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक को स्थानीय रूप से निवास करना चाहिए (अर्थात आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ किया जाना चाहिए)।
- आवेदक को शारीरिक श्रम में संलग्न होने के लिए तैयार होना चाहिए।

योजना के महत्वपूर्ण विवरण:

- राज्य सरकारों के सहयोग से, भारतीय ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) इस पहल के पूर्ण कार्यान्वयन की देखरेख की जिम्मेदारी है।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, छोटे या सीमांत किसान, भूमि सुधार से लाभान्वित होने वाले या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना से लाभान्वित होने वाले लोग व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख कार्यों को विचार के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं।
- आवेदक को अपना आवेदन जमा करने के 15 दिनों के भीतर या श्रम की आवश्यकता वाले पहले दिन एक भुगतान नौकरी की पेशकश प्राप्त होगी।
- यदि आवेदन करने के पन्द्रह दिनों के भीतर या काम की मांग की तिथि से कोई रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो आवेदक बेरोजगारी लाभ का हकदार है।
- मनरेगा कार्यक्रमों के लिए जबरन सोशल ऑडिट कराना जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

- दिहाड़ी मजदूरों के लिए अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और अनुरोध करने का प्राथमिक मंच ग्राम सभा है।
- मनरेगा परियोजनाओं की सूची को ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जो परियोजनाओं की प्राथमिकता भी निर्धारित करते हैं।

ग्राम सभा क्या करती है?

- यह ग्राम सभा की बैठकों के दौरान पड़ोस की क्षमता और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्य के सापेक्ष महत्व को स्थापित करता है।
- जीपी में किए जा रहे कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करें।

मनरेगा के तहत राज्य सरकार के दायित्व:

- राज्य की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सृजन एवं प्रचार-प्रसार करना। यह उन दायित्वों में से एक है जो अधिनियम की धारा 32 राज्य पर डालता है।
- राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) को चालू करना।
- मनरेगा को संचालित करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों के साथ एक राज्य स्तरीय मिशन या एजेंसी की स्थापना करें।
- राज्य स्तर पर एक मनरेगा सोशल ऑडिट एजेंसी या निदेशालय की स्थापना करें जिसमें पर्याप्त संख्या में ऐसे व्यक्ति हों जो कार्यक्रम के दिशानिर्देशों से परिचित हों और जिन्होंने सोशल ऑडिट के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई हो।
- एक राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना और संचालन (SEGF) किया जाना चाहिए।

- ***स्रोत→ पीआईबी***

3. - धन शोधन निवारण अधिनियम के बारे में:

जीएस III

विषय→भारत की आंतरिक सुरक्षा

मनी लॉन्ड्रिंग: यह क्या है?

- मनी लॉन्ड्रिंग गैरकानूनी गतिविधि के माध्यम से प्राप्त धन बनाने की प्रक्रिया है - जैसे कि आतंकवाद का समर्थन करना या अवैध पदार्थों से निपटना - एक वैध स्रोत से आया प्रतीत होता है। सफाई प्रक्रिया के लिए धन्यवाद, चोरी का पैसा "साफ" लगता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

- इसे वियना कन्वेंशन के भारत के पालन और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए अतिरिक्त वैश्विक पहल के जवाब में लागू किया गया था।
- पीएमएलए 2002 में पारित किया गया था और 2005 में मनी लॉन्ड्रिंग (अवैध धन को कानूनी में परिवर्तित करने) को रोकने और मनी-लॉन्ड्रिंग के माध्यम से प्राप्त संपत्ति को जब्त करना संभव बनाने के लक्ष्य के साथ लागू हुआ।

PMLA के तीन प्राथमिक लक्ष्य हैं:

- मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और विनियमित करना।
- मनी लॉन्ड्रिंग द्वारा प्राप्त किसी भी संपत्ति की जब्ती और जब्ती आवश्यक है।
- भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित किसी भी अतिरिक्त मुद्दे से निपटने में मदद करें।

विवाद समाधान:

- संघीय सरकार निर्णायक प्राधिकरण का चयन करती है। यह निर्धारित करता है कि जब्त की गई या कुर्क की गई संपत्ति का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा रहा है या नहीं।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा उल्लिखित पद्धति से विवश होने के बजाय, निर्णायक प्राधिकरण पीएमएलए के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा और प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों द्वारा शासित होगा।
- अपीलीय न्यायाधिकरण: सरकार न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण बुला सकती है। उपयुक्त उच्च न्यायालय न्यायाधिकरण के निर्णयों की अपीलों की सुनवाई करेगा।
- प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, केंद्र सरकार को एक विशेष अदालत (पीएमएलए) स्थापित करने का अधिकार देता है।

पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम 2012:

- एक "रिपोर्टिंग इकाई" के विचार का परिचय देता है, जो एक बैंक, दलाल या कोई अन्य वित्तीय संस्थान हो सकता है।
- अधिकतम जुर्माना रु. 2002 के पीएमएलए के तहत लगाए गए 5 लाख को संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था।
- ऐसी कार्रवाइयों में शामिल किसी व्यक्ति की संपत्ति अस्थायी रूप से ली और कुर्क की जाती है।

- ***स्रोत→ द इकोनॉमिक टाइम्स***

4. - प्रवर्तन निदेशालय का विवरण:

जीएस II

विषय→सांविधिक और गैर-सांविधिक निकाय

प्रवर्तन निदेशालय के बारे में जानकारी:

- यह एक बहु-विषयक संगठन है जिसे 1999 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), एक विशेष वित्तीय कानून और 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों को बनाए रखने का काम सौंपा गया है।

ऐतिहासिक संदर्भ:

- 1947 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA '47) के अनुसार, आर्थिक मामलों के विभाग ने मूल रूप से 1 मई, 1956 को इस निदेशालय की स्थापना की, जब इसने विनिमय नियंत्रण कानून के उल्लंघन से निपटने के लिए एक "प्रवर्तन इकाई" की स्थापना की।
- 1957 में संगठन का नाम "प्रवर्तन निदेशालय" में संशोधित किया गया था। 1960 तक, आर्थिक मामलों का विभाग निदेशालय को चलाने का प्रभारी था; इसके बाद राजस्व विभाग ने मोर्चा संभाल लिया।
- निदेशालय को चार साल (1973-1977) की संक्षिप्त अवधि के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रशासित करना भी जारी रखा गया।

दो क़ानूनों को लागू करना प्रवर्तन निदेशालय की ज़िम्मेदारी है:

- फेमा, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण वाला एक नागरिक कानून, एक्सचेंज कंट्रोल कानूनों और विनियमों के कथित उल्लंघनों को देखने का प्रभारी है और उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने का अधिकार रखता है।
- मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल एक्ट (पीएमएलए) के रूप में जाना जाने वाला एक आपराधिक कानून अधिकारियों को अनुसूचियों के अपराधों के परिणामस्वरूप प्राप्त संपत्ति को खोजने, अस्थायी रूप से संलग्न करने या जब्त करने के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रर्स को पकड़ने और दंडित करने के लिए जांच करने का अधिकार देता है।

संयोजन:

- निदेशालय कर्मचारियों को सीधे काम पर रखने के अलावा, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर और पुलिस सहित कई जांच संगठनों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करता है।

अन्य सूचना:

- 2018 भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के अनुसार भारत से भगोड़ों के मामलों का प्रसंस्करण।
- 1974 विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन को प्रोत्साहित करें जिसके परिणामस्वरूप निवारक निरोध (COFEPOSA) होता है।

विशेष अदालतें:

- केंद्र सरकार पीएमएलए की धारा 4 (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहयोग से) द्वारा दंडनीय अपराधों वाले मामलों की सुनवाई के लिए एक या अधिक सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नियुक्त करती है।
- PMLA कोर्ट कोर्ट का दूसरा नाम है।
- पीएमएलए अदालत के फैसले के जवाब में, उस क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय में सीधी अपील की जा सकती है।

- *स्रोत→ हिन्दू*

संपादकीय विश्लेषण

1. बैंकों का निजीकरण क्यों किया जाना चाहिए:

निजीकरण के बारे में:

- निजीकरण स्वामित्व, संपत्ति या व्यवसायों को जनता से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। व्यवसाय या उद्यम अब सरकार के स्वामित्व में नहीं है।
- निजी स्वामित्व वाले व्यवसायों की सरकार द्वारा संचालित व्यवसायों की तुलना में, निजीकरण का मतलब कंपनी की दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ाने के लिए है।
- 1991 के अपने ऐतिहासिक सुधार बजट में, जिसे आमतौर पर "नई आर्थिक नीति" या "एलपीजी नीति" के रूप में संदर्भित किया जाता है, भारत निजीकरण के लिए चुना गया।

निजीकरण के लिए ये मकसद क्यों मौजूद हैं?

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति: वर्षों के पूंजी प्रवाह और शासन में वृद्धि के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।
- उनमें से कुछ मुट्ठी भर न केवल लाभप्रदता, बाजार पूंजीकरण और लाभांश भुगतान इतिहास के मामले में निजी बैंकों से पिछड़ गए, बल्कि उन बाद के संगठनों की तुलना में तनावग्रस्त संपत्तियों का प्रतिशत भी अधिक था।

दीर्घकालिक परियोजना घटक:

- एक लंबी अवधि की रणनीति जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों की केवल एक छोटी संख्या की आवश्यकता होती है, अन्य के साथ या तो मजबूत बैंकों के साथ एकीकृत किया जा रहा है या निजीकरण किया जा रहा है, दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के साथ शुरू होगा।
- सरकार के निजीकरण की मंशा का प्रारंभिक लक्ष्य चार था। सरकार अगले दो या तीन बैंकों को अगले वित्तीय वर्ष में बेच सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पहले दो बैंक कितने सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं।
- सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में, यह सरकार को बैंकों को वार्षिक इक्विटी सहायता देना जारी रखने के अपने कर्तव्य से मुक्त कर देगा।
- पिछले कुछ वर्षों में की गई कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप एक समय में 28 राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों में से केवल 12 सरकारी नियंत्रण में मौजूद हैं।
- बैंक सुदृढ़ीकरण: कमजोर बैंकों की संख्या को कम करने के लिए सरकार कमजोर बैंकों का निजीकरण करने और मजबूत बैंकों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।
- कई समितियों की सिफारिशें: नरसिम्हम समिति ने सार्वजनिक बैंकों के सरकार के स्वामित्व को 51 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत करने की सिफारिश की।
- पीजे नायक समिति ने 50% से कम के परिणाम की सलाह दी।
- कॉरपोरेट संगठनों के लिए बैंकिंग उद्योग में प्रवेश करने के लिए आरबीआई वर्किंग ग्रुप की एक हालिया सिफारिश थी।

- विशाल बैंक स्थापना: बड़े बैंकों की स्थापना निजीकरण का एक और लक्ष्य है। अंत में, निजीकृत PSB केवल पहले से मौजूद महत्वपूर्ण निजी बैंकों के साथ विलय करके अपनी जोखिम उठाने की क्षमता और उधार क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक आकार और पैमाने तक विस्तार कर सकते हैं।
- इसलिए, निजीकरण एक चुनौतीपूर्ण प्रयास है जिसमें कई मुद्दों को हल करने और नए विचारों को ध्यान में रखने के लिए एक विविध रणनीति की आवश्यकता होती है, लेकिन यह एक अधिक भरोसेमंद और टिकाऊ वित्तीय प्रणाली के निर्माण का द्वार खोल सकता है जो सभी हितधारकों को लाभान्वित करता है।

क्या चिंताएँ संबंधित हैं?

- क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए पुरस्कार: निजी कंपनियों को पीएसबी बेचना, जिनमें से कई ने पीएसबी ऋण नहीं चुकाया है, केवल लाभ होगा और क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए एक इनाम होगा।
- रोजगार का नुकसान: निजीकरण से छंटनी, शाखा बंद और वित्तीय एकांत होगा।
- निजीकरण के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार की संभावनाएं कम हो सकती हैं क्योंकि निजी क्षेत्र वंचित समूहों (ओबीसी) के लिए कोटा सीमा का पालन नहीं करता है।
- कमजोर समूहों का वित्तीय बहिष्करण: क्योंकि वे अधिक समृद्ध आबादी और महानगरीय/शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक आर्थिक रूप से समाज के कमजोर समूहों को बाहर करते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग को सुलभ बना दिया है।
- निजीकरण की प्रक्रिया को बैंक यूनियनों ने कॉरपोरेट डिफॉल्टरों के लिए "बेलआउट ऑपरेशन" के रूप में संदर्भित किया है।
- बड़े पैमाने पर खराब ऋण निजी क्षेत्र का परिणाम हैं। दरअसल, उन्हें इस अपराध की कीमत चुकानी होगी। लेकिन निजी क्षेत्र को बैंकों का नियंत्रण देकर सरकार उन्हें पुरस्कृत कर रही है।

लेने के लिए कदम:

- पीएसबी के प्रबंधन और शासन में सुधार किया जाना चाहिए। पीजे नायक समिति ने सरकार को उच्च-स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की नियुक्तियों से रोककर ऐसा करने का सुझाव दिया (वह सब कुछ जो बैंक बोर्ड ब्यूरो को करना था लेकिन नहीं कर सका)।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अंधा निजीकरण (एलआईसी) के बजाय जीवन बीमा निगम के समान व्यवसाय में बदला जा सकता है। यह उन पर सरकारी अधिकार बनाए रखते हुए पीएसबी की स्वतंत्रता को बढ़ाएगा।

2. भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में:

जनसांख्यिकीय लाभांश की परिभाषा:

- "आर्थिक विकास क्षमता जो जनसंख्या की आयु संरचना में बदलाव के परिणामस्वरूप हो सकती है, खासकर जब कामकाजी उम्र की आबादी (15 से 64) का हिस्सा आबादी के गैर-कामकाजी-आयु वाले हिस्से (14 और उससे कम) से बड़ा है, और 65 और पुराने)," संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार, जनसांख्यिकीय लाभांश (यूएनएफपीए) के रूप में जाना जाता है।
- एक देश में काम करने की उम्र वाले लोगों का अनुपात युवा आश्रित आबादी के संबंध में बढ़ता है क्योंकि हर साल कम बच्चे पैदा होते हैं। यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन और अर्थव्यवस्था में उपयुक्त सामाजिक और आर्थिक निवेश और नीतियों को लागू किया जाता है, तो एक देश में आर्थिक विकास के अवसर की एक खिड़की होती है जिसमें कार्यबल में अधिक व्यक्ति और कम बच्चों का समर्थन होता है।

भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश:

- बूढ़ी होती दुनिया में, भारत में सबसे कम उम्र की आबादी है। भारत में, 2020 तक औसत आयु केवल 28 होगी, जबकि अमेरिका, चीन, पश्चिमी यूरोप और जापान में 37, जापान में 45 और पश्चिमी यूरोप में 49 की तुलना में।
- 2018 के बाद से, भारत में कामकाजी उम्र की आबादी आश्रित आबादी और वरिष्ठ आबादी (15 और 64 की उम्र के बीच) दोनों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। कामकाजी उम्र की आबादी अतिरिक्त 37 साल या 2055 तक बढ़ेगी।
- जीवन प्रत्याशा में वृद्धि स्थिर होने के बाद, कुल प्रजनन दर (TFR), या प्रति महिला जन्म की औसत संख्या में गिरावट आती है।
- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) द्वारा भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश के अध्ययन से दो अप्रत्याशित तथ्य सामने आए हैं।
- भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश संभावित खिड़की दुनिया की सबसे लंबी है, जो 2005-2006 से 2055-2056 तक पांच दशकों में फैली हुई है।
- इस तथ्य के कारण कि जनसंख्या कारक राज्य के आधार पर अलग-अलग तरीके से काम करते हैं, यह जनसांख्यिकीय लाभांश खिड़की विभिन्न समय पर उपलब्ध है।

जनसांख्यिकीय लाभांश के लाभ:

- काम करने वाले व्यक्तियों के अधिक अनुपात और आश्रितों के कम अनुपात के कारण बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधि ने आर्थिक प्रगति में योगदान दिया है। इसे चैनल करने के लिए निम्नलिखित चैनलों का उपयोग किया जाएगा:
- रोजगार वृद्धि, जो आर्थिक उत्पादन को बढ़ाती है।
- जनसांख्यिकीय लाभांश द्वारा दी गई अधिक वित्तीय स्वतंत्रता के कारण बच्चों से संबंधित लागतों से दूर और भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए धन को पुन: आवंटित करने की क्षमता।
- घटी हुई प्रजनन क्षमता का एक स्वाभाविक परिणाम महिलाओं के रोजगार में वृद्धि है, जो विकास के एक नए चालक के रूप में काम कर सकता है।
- चूंकि कामकाजी साल बचत करने का सबसे अच्छा समय है, बचत दरों में वृद्धि होगी।

- आकांक्षी वर्ग का उल्लेखनीय उदय या समाज का मध्यम वर्ग में परिवर्तन।
- औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में, जनसांख्यिकीय लाभांश ने ऐतिहासिक रूप से समग्र विकास में 15% तक का योगदान दिया है।
- जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पर्याप्त जनसंख्या विस्तार देखने वाले पहले विकसित देशों में से एक जापान था।
- 1964 और 2004 के बीच, राष्ट्र जनसांख्यिकीय लाभांश के दौर से गुजरा।
- तेजी से शहरीकरण और औद्योगीकरण रोजगार चाहने वाली बड़ी आबादी से पैदा होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
- कार्यबल में वृद्धि: आने वाले दशकों में, भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा और 65 प्रतिशत से अधिक कामकाजी उम्र की आबादी के कारण एशिया की संभावित श्रम शक्ति का आधे से अधिक प्रदान करेगा।
- प्रभावी नीति निर्माण: जनसंख्या गतिशीलता का उपयोग योजनाओं और कार्यक्रमों को अधिक सटीक रूप से विकसित करने और चलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे आम जनता के लिए अच्छे सामाजिक आर्थिक प्रभाव और लाभ में सुधार की उम्मीद है।

जनसांख्यिकीय लाभांश में बाधाएं:

- जनसांख्यिकीय विसंगतियाँ केवल यदि भारत अपनी कामकाजी उम्र की आबादी को सार्थक रोजगार की संभावनाएं प्रदान कर सकता है, तो जनसांख्यिकीय लाभांश पूरी तरह से प्राप्त होगा। बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी भारत के कई सबसे गरीब राज्यों में केंद्रित होने की उम्मीद है।
- ज्ञान की कमी भविष्य में सृजित होने वाले अधिकांश नए पदों के लिए उच्च स्तर की क्षमता की आवश्यकता होती है, जिससे भारतीय कार्यबल में कौशल की कमी एक महत्वपूर्ण समस्या बन जाती है। कमजोर मानव पूंजी आधार और कौशल की कमी भारत को संभावनाओं का उपयोग करने से रोक सकती है।
- यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक में भारत का 189 देशों में से 130 का चिंताजनक स्कोर मानव विकास के लिए देश के खराब मानकों को दर्शाता है।
- कुशल और उत्पादक भारतीय कार्यबल बनाने के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानकों में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है।
- अपने जनसांख्यिकीय परिवर्तन से भारत की क्षमता हासिल करने में एक और बाधा देश का अनौपचारिक क्षेत्र है।

क्या किया जाए?

- आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, गंभीर गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समावेश को बढ़ाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कौशल में निवेश करना आवश्यक है।
- युवाओं को अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल निर्माण भारत में श्रम शक्ति को समकालीन अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल में प्रशिक्षित किया जाना है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की स्थापना सरकार द्वारा 2022 तक 500 मिलियन भारतीयों को अपस्किलिंग / स्किलिंग के प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी।

- प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा के लिए बुद्धिमानी से धन आवंटित करके शैक्षिक मानकों को बढ़ाना, भारत, जहां 41% से अधिक आबादी 20 वर्ष से कम उम्र की है, जनसांख्यिकीय लाभांश से केवल तभी लाभान्वित हो सकता है जब उस देश में शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। कार्यस्थल और शैक्षणिक सीखने के स्तर की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने के लिए शिक्षाविदों और उद्योग के बीच सहयोग आवश्यक है।
- यह सही दिशा में एक कदम है कि उच्च शिक्षा वित्त एजेंसी (एचईएफए) की स्थापना की गई।
- स्वास्थ्य: एक अधिक प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली युवा श्रम बल को लंबी पारियों में काम करने की अनुमति देगी, जिससे आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- आयुष्मान भारत और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एनएचपीएस) को सफल बनाने की जरूरत है। महिलाओं और बच्चों की आहार स्थिति पर विशेष ध्यान देने के लिए एकीकृत बाल विकास (आईसीडीएस) कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए।
- कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवाओं की वृद्धि को समायोजित करने के लिए देश को हर साल 10 मिलियन नए रोजगार जोड़ने होंगे। यदि व्यावसायिक हितों और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाए तो विशाल श्रम शक्ति को रोजगार मिल सकता है।
- यह उत्साहजनक है कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- यदि अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाता है, तो स्टार्ट-अप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहल अपने उद्देश्यों को जल्दी से पूरा कर लेगी।
- शहरीकरण: युवा और कामकाजी आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भविष्य के वर्षों में अपने राज्य के अंदर और बाहर दोनों शहरों में चला जाएगा, जिससे शहरों की आबादी में तेजी से और उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह सुनिश्चित करना कि ये प्रवासी समूह शहरी सेटिंग्स में स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सहायता जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच सकें, महानगरीय नीति नियोजन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।
- स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत दोनों ही सावधानीपूर्वक और कुशल निष्पादन के लिए कहते हैं।

लेने के लिए कदम:

- यदि नीति निर्माता विकास संबंधी नीतियों को इस जनसांख्यिकीय बदलाव से जोड़ते हैं, तो भारत एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के मुहाने पर है जो इसके तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है।
- जनसांख्यिकीय लाभांश से लाभ उठाने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देने के साथ सही मानव पूंजी निवेश किया जाना चाहिए।
- जटिल समस्याएं भी इस जनसांख्यिकीय बदलाव का परिणाम हैं। यदि बढ़ी हुई श्रम शक्ति को पर्याप्त प्रशिक्षण, शिक्षा और आकर्षक अवसर प्रदान नहीं किए गए तो हमें जनसांख्यिकीय आपदा का सामना करना पड़ेगा।
- जापान और कोरिया जैसे देशों से अंतरराष्ट्रीय तरीकों का अध्ययन करके और घरेलू कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समाधान विकसित करके, हम जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने में सक्षम हो सकते हैं।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are

Vijay Kumar G

Founder and Director

Guru Deekshaa IAS

- First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
- Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
- Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

76 76 74 98 77

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

@GURU_DEEKSHAAIAS

FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

GURUDEEKSHAA